Sl. No.	Name of the Scheme	State	Installed Capacity (MW)
7.	Teesta St. II	Sikkim	373
8.	Teesta St. IV	Sikkim	495
9.	Tipaimukh	Manipur	750
10.	Dihang	Arunachal Pradesh	13400
11.	Subansiri	Arunachal Pradesh	7300
12.	Demwe	Arunachal Pradesh	520
13.	Lohit	Arunachal Pradesh	3000
14.	Kimi	Arunachal Pradesh	1100
15.	Debang Dam	Arunachal Pradesh	1000
16.	Bhopalapatnam	M.P.	1000
17.	Pimpalgaon	Maharashtra	600
18.	Mananthawadi	Kerala	240
19.	Hoganekkal	Tamil Nadu	850

विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत

1816. **श्री कपिल सिब्बल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1998 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "बाबज मेस्ड अप रिफोर्मस सेज जी०वी०आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिजली परियोजनाओं के निर्माण की लागत 2.2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक नीलामी के रूप में आंकी जाती है जबकि भारत में यह लागत 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या इससे अधिक आंकी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में परियोजना निर्माण लागत अधिक होने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (ग) विद्युत संयंत्र की लागत उसकी किस्म, क्षमता, स्थल संबंधी स्थितियों, ईंधन की किस्म संयंत्र का विस्तृत कार्यक्षेत्र और वित्त पोषण के स्वरूप पर निर्भर करता है। जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की समग्र लागत 4.2 करोड़ रु०/मे०वा० है, तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नैफ्था आधारित संयुक्त साइकिल सयंत्र की लागत में 3.0 करोड़ रु०/मे०वा० से 3.5 करोड़ रु० तक की भिन्नता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत में शुल्क और कर तथा वित्त पोषण की उच्च लागत भी शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय परिवेशी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसी संयंत्र से विशेषकर गैस टर्बाइन संयंत्रों के मामले में उत्पादन कम हो जाता है। इससे भारत में विद्युत संयंत्रों की प्रति मे०वा० लागत में और अधिक वृद्धि हो जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत अधिष्ठापित किए गए के अनुसार संपूरित लागत है। जिसमें विद्युत संयंत्रों को निर्माण हेतु सभी सिविल कार्य और सभी अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे बाह्य जल प्रणाली बाह्य ईंधन प्रहस्तन प्रणाली, ईंधन भंडारण इत्यादि शामिल हैं।

उपर्युक्त सभी घटकों की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत की तुलना विद्युत संयंत्रों के लिए दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से की जा सकती है जो कि संयुक्त साइकिल संयंत्रों के मामले में 2.0—2.3/करोड़ रु०/मे०वा० है और कोयला आधारित संयंत्रों के लिए 2.6—3.5 करोड़ रु०/मे०वा० है।

Pendings Power Projects of North Eatern Region

1817. **SHRIMATI BASANTI SARMA:** Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of the proposals for setting up of power projects in the coun-

try particularly in the North-Eastern Region pending with the Central Government;

(b) the stages at which these projects have been pending project-wise/State-wise; and

(c) the effective measures being taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARMANGALAM): (a) to (c) The details are as follows:

Project given Techno-economic Clearance by CEA:

S. No.	Name of Projects	State	Capacity (MW)	Remarks
1.	Waste Heat Recovery Unit Stage I	Assam	22.5	The Scheme was not implemented by ASEB for various reasons. ASEB has submitted a revised project report for 25 MW capacity. CEA has asked for certain clarification from ASEB.
2.	Kameng	Arunachal Pradesh	4×150 (600)	Executing Agency to be fixed.
3.	Loktak Downstream	Manipur	3×30 (90)	Cleared by CEA on 23-9-98.
4.	Dhaleshwari	Mizoram	3×40 (120)	Rejected from Environmental angle by MOEF.

Projects under Examination in CEA/CWC:

S. No.	Name of Projects	State	Capacity (MW)	Remarks
1.	Tuival	Mizoram	3×70 (210)	TEC meeting held on 17-11-1998.
2.	Myntdu (Leska)	Meghalaya	2×42 (84)	Installed capacity finalised and under examination in CEA/CWC.

A proposal of setting up 120 MW CCGT power plant at Namrup (Assam) was accorded in principle clearance of CEA on 31-3-1996 in favour of M/s Assam Valley Power Corporation Ltd., a private sector generating company. A detailed project report from the company is awaited.

बिजली की चोरी

1818. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि घाटे का एक प्रमुख कारण बिजली की चोरी और बिजली के अवैध कनैक्शन हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली की चोरी रोकने तथा अवैध कनैक्शनों को समाप्त किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?